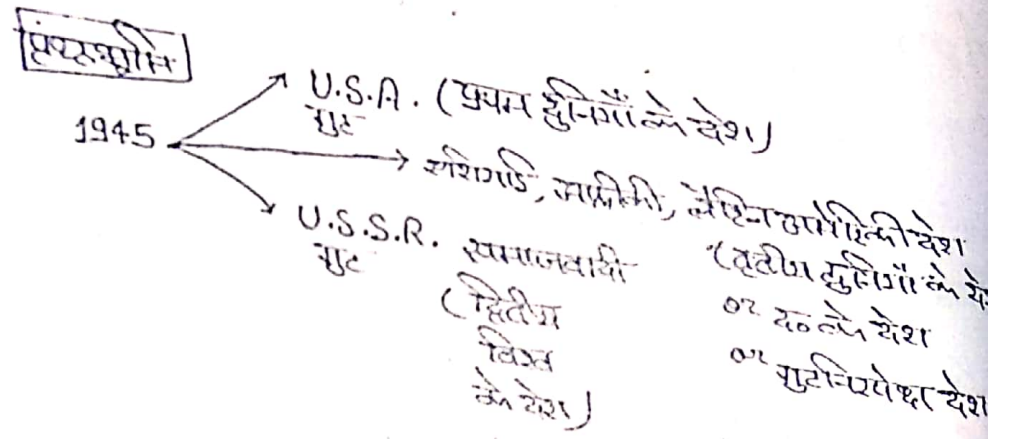
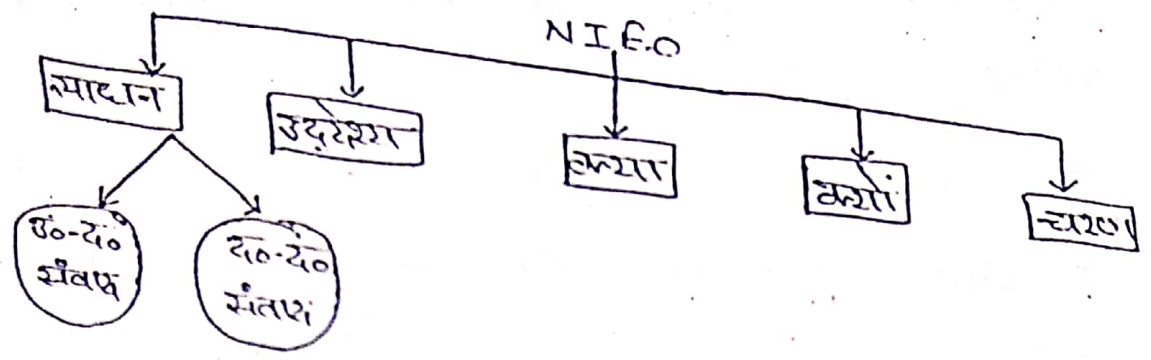


NEW INTERNATIONAL ECONOMIC ORDER (NIEO)

उ. वि. अर्थव्यवस्था और New International Eco. order



- ⇒ द्वितीय विश्व युद्ध के बाद की दुनियाँ को ब्रिटेन युद्ध सामर्थ्य का ह्रास
- ⇒ 1970 के दशक में तेल संकट, E.O. का निर्माण हो चुका था।
- ⇒ E.O. का 1974 में अपने वास्तविक विकासशील देशों के लिए बन्द कर दिया
- ⇒ 1974 में Muthy Fiber Agreement
- प्रथम-दशक - 1949-70
- द्वितीय-दशक - 1970 के बाद
- ⇒ NIEO - विकासशील देशों की माँग, ब्रिटेन युद्ध का विरोध।

नव अं. आर्थिक व्यवस्था -

विकाशशील देशों का तीसरी दुनियाँ के
सहत्वपूर्ण संगठन G-77 में अपने 32वें

वार्षिक सम्मेलन (Sep 2008) में (न्यूयार्क में) द. द. सहयोग पर
बस प्रधान करते हुए कहा कि पछितित विश्व व्यवस्था में
विकाशशील देशों के समझ गरीबी का बने घना प्रबन्ध
धुँतीपूर्ण है और यह विकसित देशों हेतु भी चिंता
का विषय है, और जोपे वतमान विश्व आर्थिक संकट
समाधान करना है तो विकाशशील देशों का विकास
करना, अपने महत्वपूर्ण मुद्दा है। वतमान वित्तीय संकट
की उत्पत्ति विकसित देशों से हुई। G-77 के देशों ने
पुनः अं. आर्थिक एवं वित्तीय संरचना के समझ
पुराकारकरण की सौदा छोड़े, इसके अन्तर्गत निम्न सौदा
सममतेत है -

- ① I.M.F. जैसे संस्थाओं में विकाशशील देशों की
भाहशासिता एवं विशेष निर्माण से बृद्धि करण।
विशेष के नष्ट मामलों की श्यापना
- ② विकसित देशों द्वारा विकाशशील देशों से ~~निवेश~~
अं. के विकास हेतु निवेश या आवाह विभाज्य।
- ③ विकाशशील देशों को उद्यम तन्वीलि का श्यानतल
विभाज्य
- ④ वार्षिक सम्मेलन अधिकार का शंशान करके हुए,
परोपणीय और जनश्रम की तन्वीलि का
माल्य मण की बलके हेतु अयोग विभाज्य
- ⑤ निम्न महत्वादि विकास तन्वीलि की वृद्धि सम्भव
हो सके।
- ⑥ परोपणीय वतमान में विकाशशील देशों के तन्वीलि का
शंशान विभाज्य

6) भारतीय विदेश नीति के अनुसार 6-77 को विकासशील देशों के साथ भारतीय सहयोग सदैव रहेगा।

I.B.S.A फोरम -

(India, Brazil, South Africa)

जिसे दिल्ली में भारत और I.B.S.A बैठक में निम्न मुद्दों पर चर्चा की गई, जो नीचे में संक्षेप रूप से प्रस्तुत हैं -

- 1) दोष निवारण वही नीति को सही और गैर सही बाजार पहुँच के मुद्दे पर, जहाँ-जहाँ हमारे निरीक्षण पर चल।
- 2) हमारे क्षेत्र के मुद्दों पर विकासशील देशों की भारतीय-नीति को ध्यान रखना।
- 3) एक-दूसरे सहयोग में हमारे क्षेत्र को दृष्टि करीबत व्यापार को लक्ष्य करवाना।
- 4) हमारे लक्ष्य हेतु विकासशील देशों द्वारा कच्ची-सामानों का हस्तान्तरण करना।

NIEO का Slogan - "Trade, Not Aid"

30-20 संवाद - विकासित - विकासशील संवाद

30-30 संवाद - विकासित - विकासित देशों के बीच संवाद

उत्तर और दक्षिण के मध्य बंदी विषमता - (WIFC. कागो डा. ॥)

द्वितीय विश्वयुद्धोत्तर युग में विकासशील देशों ने विकासशील देशों की तकनीकी और वित्तीय सहायता द्वारा औद्योगिकीकरण करने का प्रयास किया, और पहले चरण में विकासशील देशों का दृष्टिकोण अत्यधिक आशावादी था, जो विकासशील देशों की तकनीकी सहायता पर निर्भर था किन्तु अत्यधिक तथ्य में आशाहीनता सहायता प्राप्त नहीं हुई और समूहों त्रि-देशीय उल्लंघन के अन्तर्गत विकासशील देशों के हितों की उपेक्षा हुई। नोट के संघ पर समान शर्तों का निर्धारण किया गया जहाँ विकासशील देशों ने समान शर्तों का स्वीकार के अन्तर्गत व्यापार का समर्थन किया। विश्व व्यापार में व्यापार की शर्तें अर्थात् विकासशील देशों के प्रतिफल रही, जिसमें विकासशील और विकासशील देशों के मध्य शर्तों में वृद्धि हुई। विकासशील देश होने लगे जहाँ विकासशील देशों की अर्थोत्पत्ति अस्तित्व में लगी। 1964 में "UNCTAD" ने विश्व व्यापार में विषमता की ओर ध्यान दिलाया गया।

उत्तर के दशक में विकासशील देशों को अत्यधिक धिक्का हुआ और अन्तर्-निर्भरता के अन्तर्गत विकासशील देश विकासशील देशों पर निर्भर होने लगे और विकासशील देशों में व्यापार पर भी प्रभुत्व करने लगे जिससे अत्यधिक ने अपने अर्थ उद्योगिकी की सहायता दी। अतः विकासशील देशों ने इस शोषणकारी विषमतासुलभ स्थिति को विरुद्ध आवाज उठाई।

बिंदु ह्यान देस प्रोग्र ह के 1970 के दशक मे
गेट की बातों से मुक्त व्यापार पर अत्यधिक
बल दिया गया जबकि विकसित देशों ने 1974
के मन्त्रीपरिषद समीक्षा के विवादास्पद देशों
के टेकराटफल निर्मित को अपने बाजारों में
प्रतिबंधित कर दिया।

ब्रिटेनकुट्टम व्यवस्था की विवादास्पद
देशों ने खुली आलोचना की क्योंकि इस
व्यवस्था द्वारा विकसित देश अपने व्यापारिक
हितों को पूरे करने हेतु सुझावशील थे।
I.M.F द्वारा प्रकृत क्रूरताएं कर प्रतिबंध शर्तें
जारी की। I.M.F. ने आर्थिक सहायता
करने से भी राजस्व सहायता को प्रत्यक्ष
की।

तीसरा चरण या 80 का दशक -

80 के दशक को
विवादास्पद देशों हेतु विवादास्पद व्यवस्था जारी रखी
तीसरी दुनियां को भी देखा गया। 80-80 मंच पर
निर्णयान्वय रहा। सॉर्ट-संबंधित मंच तथा
पूर्व यूरोपीय राज्यों की सहायता I.M.F. द्वारा
प्रत्यक्ष रूप से की गई जिसे श्रेष्ठ
अर्थी देशों को स्पष्ट रूप से हासिल है।
अर्थात् 80 के दशक में ~~the~~ NIEO. का मुद्रा
G.T.O. के मंच पर स्थानान्तरित हो गया।

N.I.E.O. के मूल उद्देश्य -

- ① विकासशील देशों में आर्थिक तंत्र को बढ़ाना ।
- ② विकसित देशों को जो देशों को धर निर्यात को बढ़ाना ।
- ③ उच्च-कोशिका मध्य-वर्ग को बढ़ाना तथा विकसित देशों की अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ बनाना ।
- ④ विकासशील देशों को आर्थिक बहिष्कार को निवारण तथा विकासशील देशों को धर बनाना ।
- ⑤ आर्थिक अन्तर्निरीक्षण को सुदृढ़ बनाना ।

नव अर्थ आर्थिक व्यवस्था के मूल मुद्दे -

- ① आर्थिक शक्ति में सुधार
- ② विकासशील देशों को विकासशील देशों की व्यवस्था को सुदृढ़ बनाना ।
- ③ I.M.F. को I.D.P. में सुधार ।
- ④ तीव्र सुधारों को प्रणव को कोशिका को सुदृढ़ बनाना ।
- ⑤ विकसित देशों से आर्थिक, तकनीकी सहायता को कोशिका को सुदृढ़ बनाना ।

① व्यापार नव विकास -
(Trade Not Aid)

नव अर्थ आर्थिक व्यवस्था को मूल-राश व्यापार को कोशिका को सुदृढ़ बनाना । विकासशील देशों ने इन व्यवस्था को कोशिका को सुदृढ़ बनाना ।

सन् 1974 में NIEO द्वारा
 विद्यापीठ देशों ने विद्यार्थी देशों की संरक्षण
 नीतियों का विषय किया क्योंकि विद्यार्थी देश
 एक और स्थापना देने का दिखाना करते
 थे तो दूसरी ओर जापान और अन्य
 संस्थाओं का चलाना करते थे इसके अलावा
 सन् 1974 में -

- (i) 1974 का मल्टीप्लेक्स समझौता
- (ii) कच्चे पदार्थों की नीतियों को चिन्ता का
 रखना ।
- (iii) विद्यापीठ देशों की संस्थाओं को विद्यार्थी देशों
 के अलावा से चर्चने से रोकना ।

अतः विद्यापीठ देशों ने बाजार चर्च का
 मुद्दा मूल समस्या कहे जाने वाले अन्तर्गत
 अनुदान द्वारा विद्यार्थी देश अपनी रत
 आर्थिक करते हैं तथा इसके विद्यापीठ
 देशों में प्रश्न का बोझ भी बढ़ता है ।

वर्तमान स्थिति -

सामग्री की कीमतों का मुद्दा
 का विद्यापीठ देशों को समझ विद्यार्थी देशों
 के बाजारों में पहुँचने की समस्या, अल्प
 प्रमुख, विद्यार्थी देश अनेक तरीकों से अपने
 बाजारों की प्रतिस्पर्धा करते हैं -

- Ⓐ प्रशुल्कीय माध्यम
- Ⓑ गैर प्रशुल्कीय माध्यम
- Ⓒ पर्यावरणीय व श्रम मानक
- Ⓓ अल्प संख्या में नीति

② व्यापार की शर्तें

विकासशील देश मूलतः बरचसे पर्याप्त वस्तु निर्यातक हैं। अतः विकसित देशों द्वारा विनिर्मित वस्तुओं का निर्यात किया जाता है और वं व्यापार से बरचसे पर्याप्त की कीमत में अल्पविक्रय उतार - चढ़ाव देखा जाता तथा उनकी कीमत बाजार में प्रवेश के निमित्त एवं आसियर होती है। अतः व्यापार में विकासशील देशों की स्थिति तात्कालिक रूप में द्वितीयक हो जाती है। इस समस्या का समाधान लेखन अमेरिकी विचारक रॉल प्रिंसे ने सुझाया और उनके अनुसार विकासशील देशों को अपनी आर्थिक स्थिति सुदृढ़ करने हेतु स्वायत्त रूप में औद्योगिकीकरण पर बल देना होगा। उनके अनुसार विकासशील देशों की आर्थिक स्थिति बेहतर होने का मूल कारण उन्नत औद्योगिकीकरण रूप में विख्यात होता है।

समय अमीन और और गुण्डा प्रैक्क जैसे विचारकों ने यह भी आर्थिक व्यवस्था की शक्ति का अमूल्य सुझाव दिया, और उनके अनुसार पूर्णवर्षी आर्थिक प्रणाली के अन्तर्गत तीसरी दुनियाँ के देशों का विकास सम्भव नहीं है। पूर्णवर्षी व्यवस्था के विफल निर्यात की आवश्यकता है, उनके अनुसार विकासशील देशों की स्थिति में बिहर्ष होने का मूल कारण व्यापार की प्रतिफल शर्तें हैं। विकासशील देशों की अल्पविकसित स्थिति का मूल कारण विकासशील देशों द्वारा किया गया शोषण है।

जो निम्न रूप से देखा जा सकता है -

- ① विश्व बैंक का क्षेत्रीय कार्यालय अफ्रीकी तथा सुभा-मेष का निर्देशन और पश्चिमी यूरोपीय अर्थोत्थान ही हो सकता है।
- ② इन संस्थाओं में राज्यों के ^{कोटे} ~~संस्था~~ ~~उत्पन्न~~ आर्थिक योगदान के अनुपात से निर्धारित होते हैं, इन कुल 10 सांख्यिक देशों का इन संस्थाओं के मतों पर प्रभुत्व है।
- ③ विकासशील देशों की हितों इन संस्थाओं में पूर्णतः विचारित देशों पर निर्भर है।

वर्गिक 1990 के दशक से ^{विश्व} ~~विश्व~~ ~~विकास~~ संस्थाओं में पुनः संरचना की मांग उठी गई क्योंकि विकासशील देशों के अनुपात इनके प्रयोग में भी काफी है किन्तु निम्न रूप से न्याय किया जा सकता है -

- ① I.M.F. द्वारा मर्त कृपा प्रदान किया जाता है और विकासशील देशों हेतु ये शर्त अत्यधिक प्रतिबन्ध होती है।
- ② I.M.F. साथ ही गठे आर्थिक सहस्रता राजनीतिक मामलों का ^{दृष्टि} ~~दृष्टि~~ ~~निर्धारण~~ होती है। वि - 1992 के दशक ^{दशक} ~~दशक ~~दशक~~ आर्थिक संकट हेतु I.M.F. ने भारी सहस्रता प्रदान की परन्तु वर्ष 2008 में ~~वर्ष~~ ~~आर्थिक~~ ~~संकट~~ पर आर्थिक संकट पर I.M.F. ने पर्याप्त सहयोग नहीं किया।~~
- ③ शीतयुद्ध के विश्व में इन संस्थाओं का कार्य वैश्वीकरण के प्रभावित था।

शीतयुद्धोत्तर विश्व में सी बिस्वयुद्ध
 संघर्ष में सुधार की मांग व कार्यक्रम
 शीतयुद्धोत्तर विश्व में न.म.फ. द्वारा संघायित
 संघनात्मक समाशोधन कार्यक्रम की अलोकित
 हुई, विनाशशील देशों ने इसे बचाने के
 लिए शर्तों को स्वीकार किया इससे उन्हें
 कल्याणकारी कार्य सम्भावित हुए और संघनात्मक
 समाशोधन कार्यक्रम की शुरुआत की विमर्श
 में है ऐसे इसमें क्षेत्र व स्व विद्यमानियों की
 संख्या का हिसाब नहीं रखा जाता और
 सभी देशों हेतु सुधार को एक ही स्तर
 बनाए जाते हैं। शीतयुद्धोत्तर विश्व में खड़ी
 युद्ध को बाद U.S. ने कोशिश के रूप में
 कर दिए क्योंकि विश्व में खड़ी युद्ध से U.S.
 की सहायता की और शीतयुद्धोत्तर विश्व में
 विनाशशील देशों की सहायता शांति में
 और फर्सेली हुई क्योंकि न.म.फ. और
 I.B.R.D. से रकम और आर्थिक सहायता के
 पूरे गणराज्यों को आर्थिक सहायता प्राप्त
 की बिनासे एशियाई, अफ्रीकी देशों को
 लेने वाली सहायता और बच हो रही
 वर्तमान विश्व आर्थिक संकट देखते हुए
 I.N.F. की संरचना में सुधार की मांग
 पुनः उभारी हुई। विद्यमानों के अनुसार इस
 भारत एवं शान्ति जैसे विनाशशील देशों की
 सुरक्षा आर्थिक व बढ़ावा जानी चाहिए।

गैर के समीप के बाद विभाजित देशों
 में अं. व्यापार में पाठ्यपुस्तक विद्वान्त को महत्व
 दिया तो विभाजित देशों ने वीर्यता व्यापार की
 मंच उठाके और 70 के दशक में विभाजित
 देशों की व्यापार वृद्धि के लिए इसे अत्यधिक
 महत्वपूर्ण माना गया और वीर्यता व्यापार की
 यह मंच आज भी W.T.O. के मंच पर बरस
 है और W.T.O. वास्तव में विभाजित देशों
 को वीर्यता देने के बजाय विभाजित देश को
 संरक्षणकारी नीतियों अपना रहे हैं जिससे स्पष्ट
 है कि यह म. अर्थिक व्यवस्था की मंच
 आज भी प्राथमिक है बले मंच बरस रहे हैं।

कर्जवा बोझ - (1974)

विभाजित देशों ने अपने आर्थिक
 विकास के लिए आर्थिक तब में विभाजित देशों
 में विदेशी और तकनीकी सहायता प्राप्त की
 और 70 के दशक तक वे कर्ज के दुष्प्रभाव में
 पड़ गए मंच मंच मंच अर्थिक व्यवस्था
 की मंच रहे इस कर्ज के बोझ को कम
 करने की मंच सुरक्षा की। वीर्यता समय में
 मंच विभाजित विभाजित देश कर्ज के बोझ
 में रहे हैं। U.N.O. के मंच के अनुसार
 वीर्यता से अर्थिक सहायता देशों पर उठे
 G.D.P का 61% भाग प्रण के रूप में है
 जबकि वीर्यता देशों के G.D.P का 88% कर्ज के
 रूप में है।

द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से
के विकास हो रहा है। 2001 में अर्थ-दौलत
के विकास का रूप हो रहा है, अर्थ-दौलत
और विकास के बीच का संबंध। दुनिया
के विकास हो चुके हैं।

द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से
विश्वीय देशों की यह भाषा शामिल हो
गई कि गठन स्वतंत्रता का तात्पर्य विश्व
आर्थिक स्वतंत्रता होगी और विश्वीय देश
गत - साम्राज्यवाद के विचार होने लगे।
गठने वर्तमान विश्व में I.M.F. के अर्थ-दौलत के
अर्थ-दौलत के अर्थ-दौलत के अर्थ-दौलत के
दिए जो अर्थ-दौलत के अर्थ-दौलत के अर्थ-दौलत के
देशों ने विश्वीय विश्व में अपनी विकास
की योजनाओं में शामिल किए इन्होंने अर्थ-दौलत
विदेशी अर्थ-दौलत के अर्थ-दौलत के अर्थ-दौलत के
नीति बनाने हैं किन्तु अर्थ-दौलत के अर्थ-दौलत के
अर्थ-दौलत के अर्थ-दौलत के अर्थ-दौलत के अर्थ-दौलत के

तकनीकी दृष्टान्त

विश्वीय देशों की
आर्थिक दृष्टा से सुधार के अर्थ-दौलत के अर्थ-दौलत के
प्राप्त नहीं है किन्तु इन देशों का विकास
अर्थ-दौलत के अर्थ-दौलत के अर्थ-दौलत के अर्थ-दौलत के
है। इस तकनीकी पर अर्थ-दौलत के अर्थ-दौलत के
देशों का है अर्थ-दौलत के अर्थ-दौलत के अर्थ-दौलत के अर्थ-दौलत के

के माध्यम से विद्यार्थीय देशों ने अपनी-
हस्तांतरण को सुझा केन्द्रों का दिया लेकिन
विद्यार्थीय देश अपनी व्यापारिक कार करने के
तकनीकी हस्तांतरण की करते तब इसी
माध्यम से विद्यार्थीय देशों का हस्तांतरण की
करते है वो विद्यार्थीय देश अनुपयुक्त होती
है। वर्तमान क्षेत्र में तकनीकी हस्तांतरण
संघा व्यापक प्रभावकारी हो रही है, इससे
जुड़ी प्रभावकारी सिद्ध है -

- ① ^(TAIAS) वैश्विक संघर्षा उपकरणों से लाभ होने से
तकनीकी हस्तांतरण व्यापक कोर जोड़ित हो
रहे हैं।
- ② तकनीकी कर करीबने के बारी क्षेत्र
सुझा की शरा से विद्यार्थीय देश नहीं हैं।
- ③ वर्तमान क्षेत्रीय उद्योग क्षेत्रों को तकनीकी
हस्तांतरण सुझा व्यापक महत्वपूर्ण हो गया है।

बहुपक्षीय करारों - यह दो-पक्षीय करारों की संघा
में बहुपक्षीय करारों की शुरुआत को सुझा
गोरेनवा सन्घा रूप। प्रत्येकी शिक्षा-तकनीकी से
इसे अब व्यापक रूप का क्षेत्र अब। (शिक्षण
के क्षेत्र में इन बहुपक्षीय करारों की शुरुआत
आरंभ एवं शब्द दोनो क्षेत्रों से व्यापक रूप सन्घा
रही बिना सिद्ध रूपों से शुरुआत का सुझा है।

- ① बहुपक्षीय करारों से विद्यार्थीय देशों को व्यापक
करारों को सुझा शुरुआत वर क्षेत्रीय करार

विश्वी अर्थी व्यवस्था का लाभ विद्यार्थी
राष्ट्रीय को प्राप्त - करे हुआ ② बहुराष्ट्रीय व्यवस्था
में अ राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था का उद्वेगन किया।

③ अपने अर्थव्यवस्था विकास से बड़े तथा
प्रतिस्पर्धी में वसी हुई।

④ ये व्यवस्थाओं के समान संवर्धन देशों में
अपनी हुंकी काचित करती है जबकि इसका
लाभ संवर्धन देश को प्राप्त होता है।

⑤ 1970 के दशक में चीन में International
Telephone एवं Telegraph नामक कंपनी
ने अपने देशों को अर्थव्यवस्था को बड़े
महत्वपूर्ण सेवा प्रवर्धन करने को चश्वि
करने हेतु विद्यार्थी का अर्थव्यवस्था किया।

⑥ 1970 के दशक में बहुराष्ट्रीय व्यवस्थाओं
की अर्थव्यवस्था अर्थव्यवस्था के अर्थव्यवस्था
देशों में राष्ट्रीयकरण की नीति का अर्थव्यवस्था
पश्चिमी अर्थव्यवस्था देशों में भी अर्थव्यवस्था
व्यवस्थाओं के अर्थव्यवस्था का अर्थव्यवस्था किया।

⑦ अर्थव्यवस्था के अर्थव्यवस्था अर्थव्यवस्था
भूत में भी इन व्यवस्थाओं का अर्थव्यवस्था
अर्थव्यवस्था निर्माण नहीं है। अर्थव्यवस्था अर्थव्यवस्था
का अर्थव्यवस्था के अर्थव्यवस्था भी अर्थव्यवस्था के अर्थव्यवस्था
को अर्थव्यवस्था करने की अर्थव्यवस्था अर्थव्यवस्था है।

00 ① विद्यार्थीय देशों को समर्थन प्राप्त है
क्योंकि इन अतिरिक्त अवसरों के मुबालम
विद्यार्थी देशों में हैं।

वर्तमान समुदायिकता युग में
व्यवस्थापक अवसरों को प्रति विद्यार्थीय
दृष्टिकोण से परिवर्तन हुआ है। आज ये देश
ज्यादा से ज्यादा इन अवसरों को आकर्षित
करने की प्रयत्नशील हैं। Ex - 2000 में मोल्दोवा
अपनी को सात और चीन देशों ने अत्यधिक
करने का प्रयत्न किया लेकिन मोल्दोवा ने
अपना उद्यम चीन में स्थापित किया।
अतः उत्तर अमेरिका की शक्ति विद्यार्थीय ने
विशेष हेतु निजी निवेश आकर्षित करने
के प्रतिस्पर्धी कर रहे हैं।

नव अं. आर्थिक व्यवस्था पूर्ण करने के साधन -

व्यवस्था को पूर्ण करने हेतु उठ दश अंतर्गत का प्रयत्न
किया गया। इसके अन्तर्गत 1975 से पहिले अमेरिस
आधारित हुआ, जिसमें 8 विद्यार्थीय तथा 19 विद्यार्थीय
देशों ने अर्थशास्त्र को, इसके निम्न विद्युतों पर
विचार हुआ -

① विद्यार्थीय देशों ने तीसरी दुनियाँ को विद्यार्थीय वस्तुओं
के मूल्य को स्थिर करने हेतु एक विशेष कोष की
स्थापना का प्रस्ताव किया।

① अणुबम विप्रेषित देशों में विनाशशील देशों में तेल कीमतों को नियंत्रित करने की सौदा की, विशेष तेल निर्यात देशों में मना कर दिया, फलस्वरूप यह आणविक प्रकृत नहीं रहा।

नव मं. अणुबम विप्रेषण की मंत्र U.N.O. के बीच से उठी, विनाशशील देशों में अणुबम की प्रति आस्था में अणुशक्ति अनुबम केवल केवल अणुबम की शक्ति का प्रदर्शन अनुभव था। परन्तु वे इस सौदा को महाशक्ति से बाहर करना चाहते थे क्योंकि महाशक्ति में विनाशशील देशों का समावेश था। उन्मुख संवाद के मुख्य को लेकर 1977 में ब्रॉड आघात की स्थापना हुई और आघात में विनाशशील एवं विनाशशील देशों की अन्त-निर्यात पर बल दिया। आघात में निम्न मुख्य पर अपने सुझाव दिए निम्न विनाशशील देशों की स्थापना का समावेश किया जा सके -

- ① वस्तु व्यापार में वृद्धि
- ② विनाशशील देशों की अणु शक्ति अणुबम स्थापना
- ③ डॉ. सुभाषचंद्र बोस सुधार
- ④ तत्कालीन अन्तःराज्य
- ⑤ अणुशक्ति अणुबमों को अणुशक्ति अणुबम में लेकर

4) बहुपक्षीय व्यापार से विप्यामशील बुद्धि का यह है।

उस का प्रभाव है। 1981 में वास्कुन (विश्व) में सम्मेलन आयोजित हुआ, इसके 8-दिनेसम्मेलन तथा 14-दिनामशील से प्राप्त किया। प्राप्त से इस बैठक से निम्न चार सिद्धांत प्रस्तुत की -

- 1) वास्तुओं के आयात-निर्यात में शक्ति का से यह सिद्ध है समझता।
- 2) वास्तुओं के साथ निर्यात करने हेतु शक्ति के अन्तर्गत भाषों जैसे का निर्माण।
- 3) निर्यात देशों द्वारा आयात प्रतिबंधों को समाप्त करना।
- 4) 1974 के मनीषाकार समझते पर बली की आवश्यकता।
- 5) बहुपक्षीय व्यापारियों के निर्यात पर नियंत्रण की आवश्यकता।

श्री आयात ने 1983 में अपनी निर्यात प्रणाली की रूपरेखा I.M.F., I.B.R.D. तथा अन्य के साथ समन्वय को बनाया, विप्यामशील देशों से निर्यात करने की अनुमति, विप्यामशील को अधिक खेतीय आवश्यकता के का भी आवश्यक किया गया।

परिचित शक्ती (दु-दु संयोग) -

80 के दशक में विश्व में अर्थ
परिचित हो रहे थे (विश्वव्यापी) देशों की
आर्थिक दृष्टि बढ़त हुई, सोवियत संघ ने U.S.
के साथ संयोग की विदेश नीति को स्वीकारा।
उ-दु संलय के प्रभावी न होने के कारण
विश्वव्यापी देशों ने दु-दु संयोग पर बल
दिया, जिससे सामूहिक श्रमिकों और मजदूरों
संयोग द्वारा यह आर्थिक विश्व व्यवस्था को
निर्मूलक किया जा सके। यद्यपि दु-दु संयोग
का मूल आधार मुद्रास्फीति, आन्दोलन तथा
9-77 में बढ़ते ही देखते जा सकता है
परन्तु औद्योगिक रूप से इसे 1980 के
दशक में प्रभावी किया गया।

1980 में दु-दु की पहली बैठक
ने दिल्ली में हुई जिसमें विश्वव्यापी राज्यों ने
आपसी संयोग द्वारा सामूहिक आत्मनिर्भरता
प्राप्त करने का लक्ष्य रखा। 1985 में दु-दु
(एच) की बैठक में विश्वव्यापी राज्यों ने वही लक्ष्य
व्यवस्था को लागू करने पर बल दिया,
और विश्वव्यापी देशों के संघर्ष को समाप्त
करने पर भी बल दिया गया।
1987 में कोलंबो (श्री लंका) में दु-दु बैठक
हुई जिसमें मुद्रास्फीति के विदेशीकरणों ने प्रभावी
लक्ष्य तथा इस संघर्ष को समाप्त करने और
प्रभावी बनाने का 74 का है।

1989 जी कवलालम्पुर बैठक में द. के देशों ने
 एक व्यवस्थित नीतिगत समझौते के अन्तर्गत
 में सहयोग किया और औद्योगिक राज्यों
 द्वारा अपनाई जा रही दूरदृष्टिकोणी नीतियों
 का सुधार किया गया। द. के देशों ने
 इस बात पर चिंता व्यक्त की कि विकसित
 देशों द्वारा दिए जायते अनुदान की श्रेणी
 राज्यों को प्रदान हो रहे हैं।

G-15 ① स्थापना - 1989 में (बेल्जियम)

- ② 1999 में G-20 की स्थापना हुई।
- ③ G-20 में विकसित और विकासशील दोनों देशों के
 भाग लिए हैं, समूह 7 विकसित, 13-विकासशील।

④

इसका

- ⇒ I.B.S.A.
- ⇒ गंगा-मेघना चट्टीजला
- ⇒ सिमरुवेज
- ⇒ मकीमुट
- ⇒ BRIC
- ⇒ शक्ति सहयोग
- ⇒ आशियाई सहयोग

W.T.O मंच पर - G-20, G-22 मुट द. के राज्यों
 द्वारा बनाया गया।